



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 34]

नई दिल्ली, बुधस्वतिवार, मार्च 27, 2003/चैत्र 6, 1925

No. 34]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 27, 2003/CHAITRA 6, 1925

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 मार्च, 2003

सं. 311-1/2003 (इकाँन).— भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, विभिन्न सेवा प्रदाताओं के बीच अंतःसंयोजन की शर्तें नियत करने, उनके बीच प्रभावकारी अंतःसंयोजन सुनिश्चित करने तथा दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने से प्राप्त अपने-अपने राजस्व की भागीदारी के लिए सेवा प्रदाताओं के बीच व्यवस्था नियंत्रित करने के लिए, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2000 द्वारा यथासंशोधित भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 11(1) की उपधारा (ख) के खंड (ii), (iii) तथा (iv) के साथ पठित धारा 36 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित विनियम बनाता है :—

दूरसंचार अंतः संयोजन

उपयोग प्रभार (प्रथम संशोधन) विनियम, 2003

(2003 का कमांक 2)

खंड I

शीर्षक, विस्तार और प्रारंभ

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ

(i) इस विनियम का नाम “दूरसंचार अंतःसंयोजन उपयोग प्रभार (प्रथम संशोधन) विनियम 2003” होगा।

(ii) यह विनियम सरकारी राजपत्र में इसकी अधिसूचना की तारीख से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

खंड II

2.1 दूरसंचार अंतःसंयोजन उपयोग प्रभार विनियम 2003 के खंड-IV के भाग 4 में, उपभाग (iv) को मिटाकर उसके स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा:

"(iv) आई यू सी के वास्तविक रूप में लागू होने की तारीख 1 मई 2003 होगी।

2.2 दूरसंचार अंतःसंयोजन उपयोग प्रभार विनियम 2003 के खंड-IV के भाग 4 में उपभाग (v) को मिटाकर उसके स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा:

"(v) इंटरकनेक्टिंग नेटवर्कों के बीच यदि कोई राजस्व भागीदारी व्यवस्था अथवा अंतःसंयोजन (इंटरकनेक्शन) उपयोग प्रभार व्यवस्था विद्यमान है तो वह विनियम में विनिर्दिष्ट मर्दों के संबंध में केवल 30 अप्रैल 2003 तक ही प्रभावी रहेगी।

2.3 दूरसंचार अंतःसंयोजन उपयोग प्रभार विनियम 2003 के खंड-IV के भाग 4 में, उप भाग (vi) को मिटाकर उसके स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा:

"(vi) इस तारीख तक विद्यमान समस्त अंतःसंयोजन समझौतों / व्यवस्थाओं को आई यू सी व्यवस्था के अधिसूचित फ्रेमवर्क से सुसंगत करते हुए 1 मई 2003 से संशोधित माना जाएगा ताकि ये आई यू सी व्यवस्था की विद्यमान संरचना के अनुरूप हों और इन्हें 16 मई 2003 तक पंजीकरण के लिए, तथा रिपोर्टिंग की आवश्यकता के अनुसार परिवर्तनों के लिए टी आर ए आई को प्रस्तुत किया जाएगा।

खंड III**3. व्याख्यात्मक ज्ञापन**

इस विनियम में अनुलग्नक क पर एक व्याख्यात्मक ज्ञापन दिया गया है जो इस विनियम से जुड़े मामलों पर स्पष्टता और पारदर्शिता प्रदान करता है।

आदेशानुसार,

डा. रूपा आर. जोशी, सलाहकार (आर्थिक)
[विज्ञापन III/IV/142/2002/असा.]

अनुलग्नक - क**व्याख्यात्मक ज्ञापन**

1. दिनांक 24.01.2003 को जारी अंतःसंयोजन उपयोग प्रभार आई यू सी (IUC) विनियम में, शुरु में यह परिकल्पना की गई थी कि आई यू सी व्यवस्था 1.4.2003 से कार्यान्वित हो जाएगी। अतः सेवा प्रदाताओं से यह अपेक्षित था कि वे, "टी टी ओ" याने दूरसंचार टैरिफ आदेश के 24वें संशोधन के अनुरूप और 'आई यू सी' विनियम से सुसंगत, टैरिफ योजनाएं प्रस्तुत कर दें।
2. 10 से 24 मार्च 2003 के दौरान, सेवा प्रदाताओं से विभिन्न प्रकार की प्रस्तावित वैकल्पिक टैरिफ योजनाएं हमें मिलीं। इन पर विस्तार से विचार-विमर्श/संशोधन आदि जरूरी है। इन्हें संबंधित सेवा प्रदाताओं को बता दिया गया है और उन्हें कहा गया है कि वे इन्हें 'टी टी ओ' के 24वें संशोधन की व्यवस्थाओं के अनुरूप करके, और 'आई यू सी' व्यवस्था से सुसंगत बनाकर, इन टैरिफ योजनाओं को प्रस्तुत करें। उपरोक्त के अलावा, यह भी एक तथ्य है कि, टी टी ओ के 24वें संशोधन में वर्णित मानक टैरिफ के अनुसरण में, और इसके परिणामस्वरूप प्रस्तावित वैकल्पिक टैरिफ योजनाओं से उपलब्ध विकल्पों के बारे में उपभोक्ताओं को जानकारी देना आवश्यक है, प्राधिकरण ने अनुभव किया कि विभिन्न सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रस्तुत विविध योजनाओं की काफी समय रहते अंत्य उपभोक्ता याने 'एंड यूजर' को सूचना देना उपभोक्ताओं के हित में होगा, यह अपेक्षा की गई कि सारी ही टैरिफ योजनाएं 3.4.2003 तक प्राधिकरण को भेज दी जाएं ताकि वे 1.5.2003 तक लागू हो सकें।
3. प्राधिकरण का टैरिफ आदेश और अंतःसंयोजन उपयोग प्रभार (आई यू सी) दोनों परस्पर संबंध व्यवस्था की तरह विनिर्दिष्ट हैं, और इसलिए इन दोनों को साथ साथ कार्यान्वित किया जाना है।
4. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, कार्यान्वयन तिथि अर्थात् लागू होने की तारीख को अब 1.5.2003 किया गया है। इसके परिणामस्वरूप, आई यू सी विनियम से सुसंगत राजस्व भागीदारी के सभी समझौतों को अब, अधिक से अधिक 16 मई 2003 तक, प्राधिकरण को प्रस्तुत कर देना जरूरी है।

TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA**NOTIFICATION**

New Delhi, the 27th March, 2003

No. 311-1/2003-Econ.—In exercise of the powers conferred upon it under section 36 read with clauses (ii), (iii) and (iv) of sub-section (b) of Section 11 (1) of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 as amended by TRAI (Amendment) Act, 2000, to fix the terms and conditions of interconnectivity between Service Providers, to ensure effective interconnection between different service providers and to regulate arrangements amongst service providers of sharing their revenue derived from providing telecommunication services, the Telecom Regulatory Authority of India hereby makes the following Regulation.

**THE TELECOMMUNICATION INTERCONNECTION USAGE CHARGES (IUC)
(FIRST AMENDMENT) REGULATION, 2003 (2 of 2003)**

Section I

Title, Extent and Commencement

1. Short title, extent and commencement:

- (i) This Regulation shall be called "The Telecommunication Interconnection Usage Charges (IUC) (First Amendment) Regulation 2003".
- (ii) The Regulation shall be deemed to have come into force from the date of notification in the official Gazette.

Section II

- 2.1 In clause 4 under Section IV of The Telecommunication Interconnection Usage Charges (IUC) Regulation, 2003, sub-clause (iv) shall be deleted and substituted by the following:

“(iv) The date of effect for actual implementation of IUC shall be 1st May, 2003.

- 2.2 In clause 4 under Section IV of The Telecommunication Interconnection Usage Charges (IUC) Regulation, 2003, sub-clause (v) shall be deleted and substituted by the following:

“ (v) The existing revenue sharing arrangement or Interconnection Usage Charges arrangement, if any, between the Interconnecting networks shall hold good only up to 30th April, 2003 in respect of the items as specified in the Regulation.

- 2.3 In clause 4 under Section IV of The Telecommunication Interconnection Usage Charges (IUC) Regulation, 2003, sub-clause (vi) shall be deleted and substituted by the following:

(vi) All existing interconnect agreements/arrangements as on date shall stand amended on 1st May, 2003 so as to conform to the notified framework of the IUC regime and these shall be submitted to TRAI for registration by 16th May, 2003, and for subsequent changes as per reporting requirement.”

Section III

3. Explanatory Memorandum

This Regulation contains at Annex A, an explanatory memorandum to provide clarity and transparency to matters covered under this Regulation.

By Order,

DR. ROOPA R. JOSHI, Advisor (Economic)

[ADVT. III/IV/142/2002/Exty.]

871 GI/03-2

Annexure- A**EXPLANATORY MEMORANDUM**

1. The IUC Regulation issued on 24.1.2003 had initially envisaged the implementation of the IUC regime by 1.4.2003. Service Providers were thus to file tariff plans in consonance with 24th Amendment to TTO in conformity with IUC Regulation as well.
2. The various proposed alternative tariff plans have been received from service providers during the period 10th to 24th of March, 2003 and need detailed consideration / revision. These have been communicated to the service providers concerned and they have been required to file tariff plans in consonance with the IUC regime to the Authority complying with the provisions of the 24th Amendment to the TTO. In addition to the above, the fact that consumers need to be informed on the choices available pursuant to the contours of the Standard Tariff Plan outlined in 24th Amendment to TTO and the consequent alternative tariff plans, the Authority felt that it would be in the interests of the consumers that end users are informed well in advance about the various plans by different service providers, for which all tariff plans should be filed with the Authority by 03.04.2003 to be implemented by 01.05.2003.
3. The Authority's Tariff Order and the Interconnection Usage Charges Regulation were specified as Inter-linked regimes, and therefore should be implemented together.
4. In view of the above, the date of implementation for the IUC Regulation is also now 01.05.2003. Consequent to the above, all revenue sharing agreements which are in line with the IUC Regulation will now need to be filed with the Authority latest by 16th May, 2003.